पटना में प्रोफेसर भर्ती पर संग्राम

लोकभवन मार्च में पुलिस से भिड़े अभ्यर्थी

19 दिन से आमरण अनशन कर रहे शोधार्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, हिरासत में लिया

पटना, 22 अगस्त. बिहार में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली 2026 को लेकर चल रहा विरोध शनिवार को सड़क पर उतर आया. ऑल पीएचडी होल्डर एंड रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने गर्दनीबाग से लोकभवन की ओर मार्च शुरू किया.

पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कई स्थानों पर बैरिकेड लगाए थे. बेली रोड पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच तनाव बढ़ गया और अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी.

संगठन के अनुसार, अभ्यर्थी पिछले 19 दिनों से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं. आंदोलन का नेतृत्व डॉ. कुंदन कुमार कर रहे हैं. उनका कहना है कि लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे शोधार्थियों की समस्याओं को सरकार को गंभीरता से सुनना चाहिए. प्रदर्शनकारियों ने नई भर्ती व्यवस्था में कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई है. अभ्यर्थियों के मुताबिक, प्रस्तावित नियमावली में अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष से घटाकर 40 वर्ष किए जाने से वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे लोगों के सामने अवसर सीमित हो जाएंगे.

संगठन आयु सीमा फिर 55 वर्ष किए जाने की मांग कर रहा है. प्रदर्शनकारियों ने स्थायी नियुक्ति के बजाय संविदा व्यवस्था के प्रावधान पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में लगभग तीन दशकों के दौरान सहायक प्राध्यापक की भर्ती सीमित अवसरों पर हुई है. ऐसे में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. शोधार्थियों ने यूजीसी के टेबल 3 के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया लागू करने और रिसर्च पब्लिकेशन के अंकों को फिर शामिल करने की मांग रखी है. उनका दावा है कि पिछली भर्ती प्रक्रिया में शोध प्रकाशन के लिए 10 अंक निर्धारित थे.

आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का एक्शन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर यूजीसी के इक्विटी नियम और जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ जुटे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने शुक्रवार देर शाम हटाना शुरू कर दिया. उन्हें बसों में भरकर मौके से हटाया गया. दरअसल, प्रदर्शनकारी मौजूदा जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और सरकारी योजनाओं में आर्थिक आधार को ज्यादा महत्व देने की मांग कर रहे थे. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे यूजीसी और एससी-एसटी से जुड़े प्रावधानों को लेकर भी अपनी मांगें सरकार के सामने रखना चाहते हैं.

जमीन घोटाले में घिरे तेलंगाना सीएम रेड्डी

लोकायुक्त में 200 करोड़ की भूमि का मामला पहुंचा

हैदराबाद, 22 अगस्त. भारत राष्ट्र समिति ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लगभग 200 करोड़ की कीमती सरकारी जमीन अपने भाई की कंपनी को मात्र 7 करोड़ रुपये की मामूली कीमत पर आवंटित की.

यह शिकायत केस नंबर 835/2026 के तौर पर दर्ज की गई है. हैदराबाद के पास प्रस्तावित 'फोर्थ सिटी' इलाके में रविर्याला में टेसेरैक्ट एडवांस्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को लगभग 5 एकड़ जमीन आवंटित करने के मामले पर केंद्रित है. बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव, जो इस मामले में पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने सरकार पर परिवार द्वारा संचालित, परिवार-केंद्रित, बिना किसी इनोवेशन और बिना किसी कर्मचारी वाली घोटाला योजना चलाने का आरोप लगाया है. उन्होंने आवंटन के लिए पात्रता मानदंडों और निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में पूरी पारदर्शिता की मांग की है.जमीन आवंटन के खिलाफ बीआरएस का मामला टेसेरैक्ट एडवांस्ड सिस्टम्स की साख पर केंद्रित है. रामा राव ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया है कि जिस कंपनी की पेड-अप कैपिटल केवल एक लाख रुपये है और जिसकी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कोई कर्मचारी नहीं है, वह इतनी महंगी सरकारी जमीन के लिए कैसे योग्य हो सकती है. उन्होंने मंत्री दुड्डिला श्रीधर बाबू के उस दावे को खारिज कर दिया है कि मुख्यमंत्री के भाई का कंपनी से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने अनुमुला कोंडल रेड्डी की अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बयानों का हवाला दिया है, जिनमें उन्हें कंपनी का चेयरमैन बताया गया है.

उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा और पिछली बीआरएस सरकार के घोटालों से ध्यान हटाने के लिए रचा गया राजनीतिक ड्रामा करार दिया है. टेसेरैक्ट को ज़मीन का आवंटन इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पर सलाहकार समिति द्वारा पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से और सभी निर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हुए किया गया था.

तीस्ता-सिंधु पर भारत को घेरने की तैयारी

नई दिल्ली, 22 अगस्त. तीस्ता से लेकर सिंधु तक, भारत के दोनों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश पानी को हथियार बनाकर एक जैसी कूटनीतिक रणनीति अपनाते दिख रहे हैं.

बांग्लादेश के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर शाहिद उद्दीन चौधरी अनी ने भारत से गंगा जल संधि में गारंटी क्लॉज जोड़ने और साथ ही तीस्ता नदी का पानी देने की मांग की है. उन्होंने खुलकर धमकी दी है कि अगर भारत नहीं माना तो बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र समेत अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचेगा. इससे पहले पाकिस्तान भी सिंधु

भारत के खिलाफ पड़ोसियों की वॉटर डिप्लोमेसी तेज

जल संधि को लेकर यूएन सुरक्षा परिषद में जा चुका है. दोनों देशों की भाषा और रणनीति में साफ समानता दिख रही है, जिससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या भारत के खिलाफ पानी के मुद्दे पर कोई साझा मोर्चा तैयार हो रहा है. बांग्लादेश के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर शाहिद उद्दीन चौधरी अनी ने 19 अगस्त को ढाका में एक सेमिनार में यह मांग रखी. उन्होंने कहा कि गंगा जल संधि जब रिन्यू होगी तो उसमें गारंटी क्लॉज़ जरूर शामिल किया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि 1977 की संधि में यह क्लॉज मौजूद था, लेकिन 1996 में शेख हसीना सरकार के दौरान हुई तीस साल की संधि में इसे हटा दिया गया. यही संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है और मौजूदा संधि में कोई गारंटी क्लॉज नहीं है. मंत्री ने इसे बांग्लादेश का अधिकार बताते हुए कहा कि बिना संधि के आगे कोई रास्ता नहीं है. मंत्री ने यह भी कहा कि बांग्लादेश तीस्ता के मुद्दे पर भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता. लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इस फाइल की समीक्षा कर रहे हैं.

कनाडा से भिड़े ट्रंप, लगाया 50 फीसदी टैरिफ

वाशिंगटन, 22 अगस्त. कनाडा ने अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता को फिलहाल रोक दिया है. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की ओर से बातचीत के आखिरी चरण में प्रस्तावित शर्तों में किए गए बदलाव अनुचित और आर्थिक रूप से नुकसान देह थे.

यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कनाडा के साथ समझौता होने की उम्मीद जताई थी. कनाडा के फैसले से गुस्साए ट्रंप ने उस पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की है. पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच बातचीत में प्रगति हुई थी. हालांकि, कनाडा अपने प्रमुख लक्ष्यों को हासिल करने की स्थिति में नहीं पहुंच पाया. कनाडा चाहता था कि ज्यादातर कनाडाई कारोबारों को अमेरिकी बाजार में टैरिफ-मुक्त पहुंच मिले. प्रमुख उद्योगों पर अमेरिकी टैरिफ कम किए जाएं. छोटे और मध्यम आकार के कारोबारों को संरक्षण मिले. कार्नी ने कहा कि अमेरिका की ओर से आखिरी समय में प्रस्तावित शर्तों में बदलाव ने किसी संभावित समझौते की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए. कार्नी ने कनाडा के व्यापार वार्ताकारों को ओटावा लौटने का निर्देश दिया है. कनाडाई लोगों के हितों की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन अमेरिका की प्रस्तावित शर्तों में आखिरी समय में हुए बदलाव अनुचित और आर्थिक रूप से अव्यावहारिक थे.

वाराणसी के 84 घाट डूबे

गंगा किनारे अंतिम संस्कार हुआ मुश्किल

नई दिल्ली, 2 अगस्त. उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के बीच गंगा और घाघरा समेत छह नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. राज्य के 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. वाराणसी में गंगा का जलस्तर शनिवार को 68.74 मीटर तक पहुंच गया.

केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पानी करीब 20 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है. खतरे का निशान 71.26 मीटर है. जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के सभी 84 घाट डूब गए हैं. घाटों पर बने करीब 100 छोटे-बड़े मंदिर भी पानी में समा गए. मणिकर्णिका घाट की छत पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जबकि दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती भी ऊपरी हिस्से में कराई जा रही है.

प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए गंगा में छोटी-बड़ी नावों के संचालन पर रोक लगा दी है. घाटों के रास्ते और रिवरफ्रंट के कुछ हिस्से डूबने से आवागमन भी प्रभावित हुआ है. वहीं, राजधानी दिल्ली में भी रात से रुक-रुककर बारिश जारी है.

एआई का निर्माता बने भारत : सीएम गुप्ता

वेल्लोर, 22 अगस्त. भारत को केवल एआई का उपभोक्ता बने रहने के बजाय खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माता बनने की दिशा में बदलाव करना चाहिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 41वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही थीं.

समारोह की अध्यक्षता वीआईटी के कुलाधिपति जी. विश्वनाथन ने की. गुप्ता ने समारोह के दौरान स्नातक छात्रों को डिग्री प्रमाणपत्र प्रदान किए. सभा को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि जब सरकार और स्नातक मिलकर काम करते हैं, तो समाज की कई गंभीर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है. दिल्ली के अपने अनुभव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि शहर ने आईआईटी संस्थानों के साथ साझेदारी करके प्रदूषण, यातायात जाम और कचरा प्रबंधन जैसी चुनौतियों के समाधान खोजे हैं. उन्होंने स्नातक छात्रों से आग्रह किया कि कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भी इसी तरह की भूमिका निभाएं और अपने शहरों की समस्याओं के समाधान तथा देश में नवाचार में योगदान दें. उन्होंने कहा, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोगकर्ता मत बनिए, भारत की अपनी एआई का निर्माण कीजिए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा इंडिया एआई मिशन के तहत किए गए बड़े निवेश का उल्लेख किया, जिसमें सेमीकंडक्टर, कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा, रक्षा, अंतरिक्ष, ड्रोन, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी शामिल हैं.

दिल्ली में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा

एक दिन में 114 केस, अब तक कुल 1777 मामले

नई दिल्ली, 22 अगस्त. दिल्ली में इस साल अब तक स्वाइन फ्लू (एच1एन1) के 1770 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. वहीं, मानसून के दौरान मौसमी इन्फ्लूएंजा के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर स्वाइन फ्लू की स्थिति की समीक्षा की.सिंह ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी सरकारी अस्पतालों को इलाज की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि संक्रमण के पैटर्न, प्रभावित इलाकों और संभावित हॉटस्पॉट पर भी निगरानी बढ़ाई गई है. स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड तैयार किए जा रहे हैं. दिल्ली में एक ही दिन में एच1एन1 के 114 नए मरीज मिले. इससे इस वर्ष अब तक एन1एच1 की पुष्टि हुई मरीजों की संख्या बढ़कर 1,777 हो गई. छह अगस्त तक दिल्ली में एच1एन1 के 1,344 मामले थे. यानी मात्र 14 दिन में 433 नए मामले सामने आए. 20 अगस्त को मिले 114 नए मरीज दिल्ली के किन अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं, इसका ब्योरा स्वास्थ्य विभाग ने अब तक सार्वजनिक नहीं किया है.

रिश्वत मामले में मान की पत्नी ने रिटायर्ड जज को दिया नोटिस

▸ रेप मामले को दबाने का लगाया था आरोप

चंडीगढ़, 22 अगस्त. पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर को लेकर लगाए गए रिश्वत के आरोपों के बाद मामला कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट रिटायर्ड जज रणजीत सिंह ने उन पर रेप के एक मामले को दबाने के बदले 5 करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाया था. अब गुरप्रीत कौर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए रणजीत सिंह को कानूनी नोटिस भेजा है. नोटिस में गुरप्रीत कौर ने आरोपों को झूठा, निराधार और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया है. उन्होंने रिटायर्ड जज से कहा है कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर अपने बयान वापस लें और सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगें. निर्धारित अवधि में ऐसा नहीं करने पर आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दी गई है.

पुलवामा हमले की आरोपी इंशा की जमानत खारिज

श्रीनगर. पुलवामा आतंकी हमले के मामले में आरोपी इंशा जान की जमानत याचिका एनआईए अदालत ने खारिज कर दी है. अदालत ने अपने 15 पन्नों के आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री ऐसी है, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सही माना जा सकता है. विशेष न्यायाधीश प्रेम सागर ने 20 अगस्त को यह आदेश सुनाया. अदालत ने यह भी कहा कि यूएपीए की धारा 43-डी(5) के तहत मौजूद वैधानिक प्रतिबंध के कारण इस चरण में इंशा को जमानत नहीं दी जा सकती.

एक नजर में

संभल हिंसा के आरोपी शारिक पर शिकंजा

संभल. संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने शारिक साठा के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है. पुलिस के अनुसार साठा को इस मामले में मुख्य आरोपी या मास्टरमाइंड के तौर पर चिन्हित किया गया है और वह फिलहाल दुबई में मौजूद है. साठा के खिलाफ अदालत की ओर से दंड प्रक्रिया से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा चुकी है और उसे भगोड़ा घोषित किया गया है.

उबर पर लगा 8000 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली. डच डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने उबर पर 825 मिलियन यूरो (966 मिलियन डॉलर या करीब 8100 करोड़) का भारी जुर्माना लगाया है. यह मामला यूरोप के डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के नियमों के तह इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा जुर्माना है. इससे पहले साल 2023 में मेटा पर डेटा ट्रांसफर उल्लंघन के लिए 1.2 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया था.

22 भारतीय नाविकों के लिए भारत सक्रिय

नई दिल्ली. भारत ने कहा कि उसने 22 भारतीय नाविकों वाले दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा सोमालिया के अधिकारियों के समक्ष उठाया है. केन्या स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि एमटी सिबू पर 16 और एमवी लुतुफ पर छह भारतीय नाविकों के सवार होने की जानकारी मिली है. उच्चायोग ने कहा, सभी भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की खबर है. हम भारतीय नाविक समुदाय की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं. भारतीय मिशन ने कहा, हमने सोमालिया के संबंधित अधिकारियों के समक्ष एमटी सिबू (इरीट्रिया के ध्वज वाला) और एमवी लुतुफ (कैमरून के ध्वज वाला) जहाजों पर सवार भारतीय नाविकों का मुद्दा उठाया है.

हस्तियों के ट्वीट

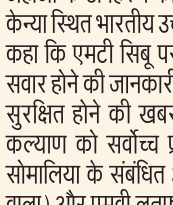

भारतीय उद्योगपति, राजनेता नवीन जिंदल ने हाल ही सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि बीजिंग ओलंपिक 2006 का वह ऐतिहासिक क्षण आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व और देशभक्ति का नया जोश भर देता है! हमारे हरियाणा की शान, देश के गौरव और प्रिय मित्र बॉक्सर विजेंदर, आपने मुक्केबाजी में देश का पहला ओलंपिक पदक जीतकर इतिहास रचा था.

वर्तमान में भारत सरकार के कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने हाल ही सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि राजनीतिक स्थिरता और नीतियों में निरंतरता की वजह से भारत में विकास और सुधार बहुत तेजी से हो रहे हैं. 21वीं सदी के भारत में, हम रेगुलेशन (नियमन) की सोच को बदल रहे हैं जब तक इजाज़त न हो, तब तक मनाही' से बदलकर 'जब तक मनाही न हो, तब तक इजाज़त की ओर.

भरोसेमंद न्याय से बढ़ेगी देश की इकोनॉमी

11 ब्रिक्स लीगल फोरम में बोले सीजेआई सूर्यकांत

नई दिल्ली, 22 अगस्त. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम में आर्थिक प्रगति और न्याय व्यवस्था के बीच संबंध पर अपने विचार रखे.

उन्होंने कहा कि किसी देश की तरक्की केवल उसके भूगोल या प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं होती. इसके लिए ऐसी कानूनी संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जो अधिकारों की रक्षा करें, समझौतों को प्रभावी ढंग से लागू कराएं और कारोबार के लिए भरोसेमंद वातावरण तैयार करें. सीजेआई ने इस संदर्भ में 'न्याय-नॉमिक्स' की अवधारणा सामने रखी. उन्होंने कानूनी संस्थाओं को विकास के बाद खड़ा होने वाला ढांचा नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति की आधारभूत संरचना बताया. उनके अनुसार, यदि न्याय व्यवस्था निष्पक्ष और निरंतर प्रभावी ढंग से काम करती है तो नागरिकों और कारोबारियों का संस्थाओं पर विश्वास मजबूत होता है. उन्होंने बताया कि न्याय व्यवस्था में भरोसे का सीधा असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है. जब अदालतों से लगातार और निष्पक्ष निर्णय मिलने की उम्मीद रहती है, तो व्यावसायिक लेनदेन में अनिश्चितता और उससे जुड़ी लागत घट सकती है.

सिर्फ प्रकृति से विकास संभव नहीं

मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स देशों के संदर्भ में कहा कि कोई भी राष्ट्र केवल प्राकृतिक संपदा के सहारे दीर्घकालिक विकास हासिल नहीं करता. आर्थिक व्यवस्था की मजबूती इस बात से भी तय होती है कि अनुबंधों, वादों और समझौतों को कानून किस स्तर तक प्रभावी सुरक्षा देता है. अपने संबोधन में उन्होंने 'न्याय सेतु' का विचार भी रखा. उन्होंने इसे 11 देशों की अलग-अलग कानूनी परंपराओं को जोड़ने वाले पुल के रूप में प्रस्तुत किया.

आज का इतिहास

1990- पूर्व-पश्चिम जर्मनी ने तीन अक्टूबर को एकजुट होने की घोषणा की.

1993- 2000 के ऐतिहासिक ओलंपिक खेलों की मेजबानी आस्ट्रेलियाई नगर सिडनी को सौंपी गई.

1994- भारतीय महिला तैराक आरती साहा का निधन.

1997- सं.रा. अमेरिका के मिसीसिपी यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर को चार साल पहले मिला हल्दी का पेटेन्ट रद्द.

2002- सं.रा. अमेरीका ने मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण रोका, इटली ने पाकिस्तान में वाणिज्य दूतावास बंद करने की धमकी दी.

अल नीनो बढ़ाएगा गर्मी, भारत में कमजोर मानसून

2027 बन सकता है दुनिया का सबसे गर्म साल

नई दिल्ली, 22 अगस्त. धरती की दहलीज पर एक बड़ा खतरा खड़ा है. दुनिया में एक बड़ा संकट दस्तक देने को बेताब है. अगर समंदर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाए और उसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ने लगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा ही खतरा इस वक्त मंडरा रहा है.

इस संकट का नाम है अलनीनो. वैज्ञानिकों ने इस साल के अल नीनो को लेकर बड़ी चेतावनी दी है. साइंटिस्ट की मानें तो इस साल का अल नीनो 100 साल से भी ज्यादा समय में सबसे ताकतवर हो सकता है. इसका असर दुनिया में रिकॉर्ड गर्मी के रूप में दिख सकता है. जब दुनिया में संकट होगा तो भारत भी कैसे अछूता रहेगा. अलनीनो के कारण भारत को कमजोर मानसून और फसलों पर असर की दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने काजीरंगा मामले में असम सरकार को तलब किया

नई दिल्ली, 22 अगस्त. काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की पर्यावरणीय सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई और निगरानी से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आने पर सवाल खड़े हो गए हैं.

पर्यावरण कार्यकर्ता रोहित चौधरी द्वारा दायर आरटीआई के जवाब से सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को असम सरकार ने काजीरंगा के नौ वन्यजीव गलियारों और 10 किलोमीटर के डिफॉल्ट ईको-सेंसिटिव जोन से जुड़ी मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है.

3 मार्च 2022 को सीईसी ने नई दिल्ली में असम के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी. यह बैठक सुप्रीम कोर्ट के 14 अप्रैल 2019 के आदेश के क्रियान्वयन को लेकर हुई थी. अदालत ने एक सींग वाले गैंडे के आवास और कार्बी आंगलोंग जिले के महत्वपूर्ण पहाड़ी जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए दक्षिणी सीमा के पास सभी तरह के खनन, पत्थर खनन और संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई थी.

चुनावी जंग ▸ जाति से आगे निकलीं यूपी की महिलाएं, भाजपा-सपा आमने-सामने

2027 से पहले महिला वोट के लिए बड़ी जंग

लखनऊ, 22 अगस्त. चुनावी रणनीतिकार चाहे जातियों की लामबंदी में लगे हों, लेकिन इस बार करीब 6.09 करोड़ महिला मतदाता सत्ता की चाबी अपने हाथ में थामे खड़ी हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 45.46 प्रतिशत हैं.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजने की होड़ मच गई है. उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास उठाकर देखें तो चुनावी गुणा-गणित हमेशा जातियों के इर्द-गिर्द घूमता रहा है- यादव, गैर-यादव ओबीसी, दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम. लेकिन 2027 के विधानसभा रण की बिसात बिछने से पहले ही एक नया और सबसे असरदार वोट बैंक उभरकर सामने आ रहा है, जो जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ रहा है. यह साइलेंट वोट बैंक है प्रदेश की महिलाएं.चुनावी रणनीतिकार चाहे जातियों की लामबंदी में लगे हों, लेकिन इस बार करीब 6.09 करोड़ महिला मतदाता सत्ता की चाबी अपने हाथ में थामे खड़ी हैं. यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव, दोनों ही 'आधी आबादी' को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे.

2012 चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत उछलकर 60.3 प्रतिशत पहुंचा, जो पुरुषों (58.7 प्रतिशत) से ज्यादा था. 2017 और 2022 दोनों ही चुनावों में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले औसतन 3 से 4 फीसदी ज्यादा मतदान किया. 2024 लोकसभा चुनाव में भी 57.22 प्रश महिला मतदाताओं ने वोट डाला, जबकि पुरुषों का आंकड़ा 56.46 प्रतिशत ही रहा. मध्य प्रदेश में 'लाडली बहना' और महाराष्ट्र में 'लाडकी बहिन' जैसी योजनाओं के दम पर जिस तरह भाजपा ने बंपर जीत दर्ज की, उसने हर राजनीतिक दल को यह समझा दिया है कि महिलाओं का साथ ही जीत की गारंटी है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिला वोटरों को एक सिंगल 'वोट बैंक' माना जा सकता है?